ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर से उत्तर प्रदेश में होगी नई औद्योगिक क्रान्ति की शुरूआत

- *₹42,000 करोड़ का निवेश सम्भावित*
- *उ.प्र सरकार का बड़ा कदम– परियोजना विकास हेतु 5 प्रतिशत् इक्विटी देने को सहमत*
- *राज्य सरकार ने चिन्हित किए तीन इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग ज़ोन*
- *फ्रेट गलियारे पर प्रदेश में बनेंगे 40 नये स्टेशन*
- *लगभग 57 प्रतिशत्, 1049 किमी लम्बा भाग उत्तर प्रदेश के 18 जिलों से होकर गुजरेगा*

लखनऊ, 16 दिसम्बर 2013

प्रदेश में औद्योगिक विकास को अभूतपूर्व गति प्रदान करने वाली ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (ई. डी.एफ.सी.) परियोजना के उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले भाग में लगभग ₹42,000 करोड़ के निवेश की सम्भावना है। इस गलियारे के विकास हेतु राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 5 प्रतिशत् इक्विटी देने को सहमत प्रदान कर दी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने तीन सम्भावित एकीकृत विनिर्माण परिक्षेत्रों **(Integrated Manufacturing Zone)** को चिन्हित करते हुए केन्द्र सरकार को सूचित कर दिया है।

ई.डी.एफ.सी. के सरेक्षण के आस–पास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की असीम सम्भावनाओं के दृष्टिगत् मा. मुख्यमंत्री, श्री अखिलेश यादव की दूरदर्शी पहल पर राज्य सरकार ने वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर पर दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की तर्ज पर ई.डी.एफ.सी. पर अमृतसर–दिल्ली–कोलकता इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर विकसित करने हेतु कॉन्सेप्ट पेपर भारत सरकार को उपलब्ध कराया है। जिसके क्रम में विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर (ई. डी.एफ.सी.) के संरेखण पर प्रस्तावित तीन क्षेत्रीय विकास क्लस्टरों को चिन्हित कर उनकी संरचना योजना तैयार करने पर सहमति व्यक्त की है। ये तीन क्षेत्र हैं– **औरैया–कानपुर** (कानपुर देहात), **इलाहाबाद–वाराणसी** (कौशाम्बी एवं संत रविदास नगर), **आगरा–अलीगढ़** (मथुरा, हाथरस एवं फिरोज़ाबाद)। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने **अमृतसर–दिल्ली–कोलकता इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर (एडीकेआईसी) में 05 प्रतिशत् इक्विटी हेतु भी सैद्धान्तिक सहमति दे दी है।**

ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर की कुल लम्बाई 1840 किमी है, जो पंजाब में लुधियाना से प्रारम्भ होकर मुख्यतः उत्तर प्रदेश में खुर्जा से होते हुए पश्चिम बंगाल में दानकुनी तक जाएगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश को अधिकतम लाभ होगा, क्योंकि इसका लगभग 57 प्रतिशत्, 1049 किमी लम्बा भाग उत्तर प्रदेश के 18 जिलों से होकर गुजरेगा, जिस पर 40 नये स्टेशन स्थापित करना प्रस्तावित है।

एडीकेआईसी के बड़े भाग के उत्तर प्रदेश में होने के कारण राज्य सरकार ने उपरोक्त क्षेत्रीय विकास क्लस्टरों में तीन एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर **(Integrated Manufacturing Clusters)** भी प्रस्तावित कर केन्द्र सरकार को सूचित कर दिया है। भारत सरकार द्वारा इन एकीकृत विनिर्माण क्लस्टरों के लिए नियत किए गए 10 वर्ग किमी के क्षेत्रफल को राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में और बढ़ाने की मंशा भी है।

प्रदेश सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इलाहाबाद को ईडीएफसी के एक अर्ली बर्ड प्रोजक्ट के रूप में स्वीकृति दिलाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके तहत इलाहाबाद में लगभग 1200 एकड़ में एक इंटीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल टाउनशिप भी प्रस्तावित है। इस दिशा में भूमि के हस्तानांतरण की प्रक्रिया चल रही है तथा ख्याति–प्राप्त आर्किटेक्ट स्टूडियो सिम्बायोसिस ने महायोजना भी तैयार कर ली है। नई टाउनशिप को संगम के आकार से मिलता–जुलता डिज़ाइन किया जाएगा जिसमें उद्योगों तथा संस्थाओं के लिये प्रचुर भूमि चिन्हित की जाएगी।

ज्ञात हो कि ईडीएफसी के तहत उच्च भार–वहन क्षमता वाली रेल पटरियाँ बिछाई जाएंगी, जिससे प्रति इकाई भार परिवहन लागत में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक तथा यथोचित मूल्य उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। इस पर 400 मीटर लम्बी मालगाड़ी के स्थान पर 1400 मीटर लम्बी मालगाड़ियाँ चलेंगी, जिससे यात्री रेलगाड़ियों के लिए रेल–पटरियाँ खाली होने से यात्री–सुविधा भी बढ़ जाएगी। राज्य सरकार द्वारा ईडीएफसी पर 06 इन्वेस्टमेंट इण्डस्ट्रियल ज़ोन प्रस्तावित किए गए थे। जिनमें इटावा–औरैया इण्डस्ट्रियल ज़ोन (6000 हेक्टेअर), पश्चिमांचल इण्डस्ट्रियल जोन (2000 हेक्ट0), ब्रज इण्डस्ट्रियल जोन (2000 हेक्ट0), कानपुर लॉजिस्टिक्स हब (6000 हेक्ट0), इलाहाबाद–नैनी–बारा इन्वेस्टमेंट जोन (3000 हेक्ट0), मुगलसराय–वाराणसी–मिर्जापुर इन्वेस्टमेंट जोन (3000 हेक्ट0) सम्मिलित हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक को इस परियोजना का नोडल अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को नोडल एजेसी नामित किया गया है।

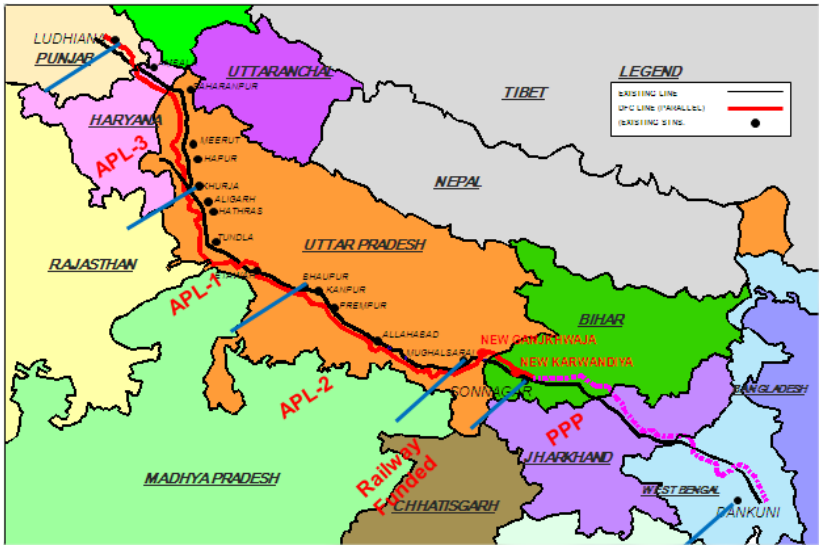

उत्तर प्रदेश में ई.डी.एफ.सी. का प्रस्तावित संरेखण